इन बंद मिलों में से 1 मिल 1967 में, एक 1970 में, दो 1976 में, दो 1981 में, आठ 1982 में, चौदह 1983 में, 16 मिल 1984 में, 7 मिल 1985 में, 33 मिल 1986 में तथा 49 मिलें 1987 में बंद की गयीं। कामगारों को उस दिन से बेरोजगार माना जाता है जिस दिन से मिल विशेष को बंद किया जाता है।

उन एककों की संख्या देना सम्भव नहीं हैं जिन्हें पुनः चालू किया गया और बाद में पुनः बंद कर दिया गया, क्योंकि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी वस्त्र मिल को कुछ समय के दौरान कुछ सहायता दिये जाने के बाद, वह स्वतः कार्य क्षम हो जायेगी। किसी विशेष समय पर वस्त्र मिलों को जीवन क्षमता अथवा अन्य बातें विभिन्न कारणों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये कारण किस समय क्रियाशील हो जायेंगे इसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

Loan melas organised by the Nationalised Banks

42. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nationalised banks have been organising melas for the distribution of loans to the needy; and

(b) if so, what is the number of such public functions for the distribution of loans to the needy organised by the nationalised banks since 1981 till 31st December, 1987, alongwith the dates, the amount disbursed on each occasion and the names of the banks which participated in these loan melas and also the places where these functions were held?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Banks organise credit camps as part of their overall measures to accelerate the flow of credit to weaker sections and also to bring about greater awareness amongst them of assistance available from banks. It is not possible to indicate the number of such camps held since no central monitoring of credit camps is considered to be either feasible or necessary. However, as at the end of September 1987, Public Sector Banks had outstanding advances of Rs. 6506.06 crores involving 2.05 crores borrowal accounts in favour of weaker sections of society.

राष्ट्रीयकृत बैंकों का आवास कार्यक्रम

43. श्री मीर्जा इर्शादबेग : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवास निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों का कितना प्रतिशत योगदान है तथा इस सम्बन्ध में उनका भावी कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1986 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आवास निर्माण के लिये वित्त प्रदान करने के वास्ते 183.09 करोड़ रुपए की रकम दी थी, जो वर्ष के अन्त में बकाया अग्रिमों का 0.34 प्रतिशत बैठती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी बताया है कि समग्र आवास वित्त नीति पर फिर से विचार किया जा रहा है और जैसे ही नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, वैसे ही भावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी।

Central assistance for the construction of canals in Rajasthan

44. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the amount of Central assistance given for the construction of canals in Rajasthan during the last three years; and

(b) the number of canals constructed in Rajasthan during this period and the acreage of land being irrigated thereby?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a)